International Journal of Sociology and Humanities

ISSN Print: 2664-8679
ISSN Online: 2664-8687
Impact Factor: RJIF 8
IJSH 2024; 6(1): 19-26
www.sociologyjournal.net
Received: 20-11-2023
Accepted: 23-12-2023

डॉ० करुणा कुमारी
राजनीति विज्ञान विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ० करुणा कुमारी
राजनीति विज्ञान विभाग
सामाजिक विज्ञान संकाय
भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत

भारत-पाकिस्तान संबंध : आजादी के 75 वर्ष बाद भी प्रतिस्पर्धा एवं वैमनस्यता

डॉ० करुणा कुमारी

DOI: https://doi.org/10.33545/26648679.2024.v6.i1a.69

सारांश
भारत और पाकिस्तान भाषाई, सांस्कृतिक, भौगोलिक और आर्थिक संबंध साझा करते हैं, फिर भी उनके संबंध कई ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाओं के कारण जटिलताओं में फंस गए हैं। भारत-पाक संबंधों को वर्ष 1947 में ब्रिटिश भारत के हिंसक विभाजन, जम्मू और कश्मीर संघर्ष और दोनों देशों के बीच लड़े गए कई सैन्य संघर्षों द्वारा परिभाषित किया गया है। ब्रिटिश भारत का विभाजन अब तक देखे गए सबसे बड़े मानव प्रवासों में से एक था और इसने पूरे क्षेत्र में शरणार्थियों के खूनी नरसंहार को जन्म दिया। वर्ष 1947 में भारत के विभाजन से 12.5 मिलियन लोग विस्थापित हुए, जिसमें 1 मिलियन लोगों की जान जाने का अनुमान है।
भारत हिंदू बहुसंख्यक आबादी और बड़ी मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी के साथ एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया, जबकि पाकिस्तान भारी मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी और अन्य धर्मों की सदस्यता लेने वाली बहुत छोटी आबादी के साथ एक इस्लामी गणराज्य के रूप में उभरा। भारत-पाकिस्तान संबंध में प्रतिस्पर्धा और वैमनस्यता भारत विभाजन से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल से भारत ने स्वतंत्रता एक लम्बे स्वतंत्रता आंदोलन के बाद प्राप्त किया है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में लोकतांत्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषायी इत्यादि तत्व निहित था। इस व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन ने आधुनिक भारत की आधारशिला की नींव रखा था। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, गणतांत्रिक एवं लोकतांत्रिक भारत की आधारशिला को रखा है। दूसरी तरफ, पाकिस्तान का निर्माण धार्मिक सांप्रदायिकता का परिणाम है। आजादी के 75 साल बाद भी पाकिस्तान एक अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और धार्मिक कट्टरता वाला देश बना हुआ है। पाकिस्तान का अलोकतांत्रिक राजनीतिक स्वरूप एवं धार्मिक कट्टरता ने दोनों देशों के संबंध में प्रतिस्पर्धा एवं वैमनस्यता को बनाए रखा।

कूटशब्द : औपनिवेशिक शासन, भारत का विभाजन, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक कट्टरता, वैमनस्यता, सांप्रदायिकता

प्रस्तावना
भारत-पाकिस्तान के संबंध को दुनिया के किसी भी दो स्वतंत्र राज्यों के बीच सबसे जटिल संबंधों में से एक माना जाता है।

दोनों देशों में आपसी संबंधों को प्रभावित करने वाले ऐसे अनेक तत्त्व हैं जो विदेश नीति में निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। दोनों देशों में परस्पर अविश्वास है, अनसुलझे मुद्दे हैं। दोनों ही देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं जिनमें परस्पर शत्रुता, आतंकवाद, और लगातार संघर्ष की स्थिति बनी रहती है जो दक्षिण एशिया के इन दो देशों की धुँधली तस्वीर बयां करते हैं। दोनों देशों की सीमाओं पर भारी सेनाओं की तैनाती कुछ और ही बात कहती है और ये एक तरह का दो व्यक्तियों के बीच खेला जाने वाला शून्य-शून्य का खेल है जहाँ किसी एक देश के लाभ का मतलब दूसरे देश का उसी अनुपात में नुकसान होना माना जाता है। दोनों देशों में समान सांस्कृतिक विरासत है, सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध हैं और कभी-कभी, भले ही सीमित संदर्भों में सही, राजनीतिक-आर्थिक सहयोग इन संबंधों को एक नया आयाम देते हैं जिससे पारस्परिक शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों की आशा की जा सकती है (दक्षिण एशिया के लिए यूरोपीय फ़ाउंडेशन 2023, पृष्ठ संख्या-1)।

भारत विभाजन के सात दशक बाद भी इस विभाजन का उद्देश्य अधूरा है। माना गया था कि अपने लिये अलग राष्ट्र की इच्छा रखनेवाले मुसलमानों की मुराद पूरी हो जायेगी, तो आशंकाओं के धुंध छंट जाएंगे, दोनों देश शांति के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होंगे। दोनों देशों के पहले सत्ता-प्रमुखों- पंडित जवाहर लाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना- की घोषित आकांक्षाएं यही थीं, लेकिन भारत-पाक संबंधों का इतिहास गवाह है कि हुआ ठीक इसके विपरीत। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान भारत से बैर रखने लगा और कश्मीर पर कब्जा करने के इरादे से युद्ध के मैदान में भारत को ललकार कर कई बार मात खायी। जब उसे आभास हो गया कि सीधे युद्ध में भारत को पराजित करना या कश्मीर पर कब्जा करना संभव नहीं है, तब आतंकवाद को पाल-पोस कर छद्म युद्ध की राह पर चल पड़ा (मेहता 2022, पृष्ठ संख्या-9)।

एक ओर पाकिस्तान का भारत से बैर आजादी के बाद से आज तक निरंतर जारी है। दूसरी ओर, भारत में सरकारों के बदलने के साथ-साथ नीतियों में उतार-चढ़ाव आता रहा। पाकिस्तान के साथ दोस्ती के मकसद से नये-नये प्रयोग हुए, उदारता दिखाते हुए कई एकतरफा समझौते किये गये। लेकिन, आज स्वतंत्र भारत की तीसरी पीढ़ी भी पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य करने की चुनौतियों से जूझ रही है। इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं कि दो राष्ट्र आम जनजीवन में गहन और विस्तृत समानताओं के बावजूद आपसी संघर्ष की स्थिति में ठहर से गये हों (मित्रा 2017, पृष्ठ संख्या-264)।

भारत-पाकिस्तान के सम्बन्धों का इतिहास अविश्वास, खण्डित वादों, अनसुलझे मुद्दों तथा असीमित संघर्षों का इतिहास है। विचारधारा से सम्बद्ध विभिन्न कारकों के विभाजनकारी प्रभाव, विभाजन की हिंसक परम्परा, पड़ोसी शत्रु की छवि तथा कश्मीर सहित अनेक अनसुलझे मुद्दों के कारण दोनों देश एक ऐसी जटिल स्थिति में उलझ कर रह गये हैं जिसमें किसी भी एक पक्ष के इच्छित लाभ को दूसरे की समतुल्य हानि के रूप में देखा जाता है (मित्तल एवं रंजन 2016, पृष्ठ संख्या-12)। भारत के पूर्व विदेश सचिव के. नटवर सिंह के अनुसार, भारत-पाकिस्तान के सम्बन्ध पाकिस्तान के लिए "दीर्घकालिक दुर्घटना सम्भावित" और इतना अधिक परिवर्तनशील तथा अनिश्चित है जिससे स्थिति का सामान्य होना असम्भव सा है।

क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान के अगस्त 2018 में सत्ता में आने के बाद उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शुभेच्छाओं का आदान-प्रदान हुआ। लेकिन इसके बाद के महीनों के दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ, जिससे दोनों देशों के बीच न सिर्फ शत्रुता को गहरा किया, बल्कि दोनों पक्षों को युद्ध के कगार पर ला दिया। सद्भावना का ये दौर कुछ समय ही चला और पाक स्थित आंतकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद द्वारा जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को 44 सीआरपीएफ सैनिकों की हत्या के साथ ही संबंध कटु हो गए (दक्षिण एशिया के लिए यूरोपीय फाउंडेशन 2023, पृष्ठ संख्या-1)।

भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया और बदला लेने की कसम खाई। हालांकि, पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। इसके बाद 26 फरवरी को भारत के लड़ाकू विमान ने पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश किया और बालाकोट स्थित जैश के शिविर पर बमबारी की। वर्ष 1971 के युद्ध के बाद यह पहला मौका था जब भारतीय युद्धक विमान ने पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश किया। इस हवाई हमले के बाद 27 फरवरी को

दोनों देशों के बीच हवाई युद्ध जारी रहा, जब पाकिस्तान के युद्धक विमान ने भारत की सीमा में प्रवेश किया।

पाकिस्तान जेट को मारने के दौरान भारतीय वायु सेना का एक जेट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और भारतीय पायलट को पाकिस्तान ने घायल अवस्था में पकड़ लिया। एक पल के लिए ऐसा लगा कि दोनों देशों की दुश्मनी अब चरम पर पहुंच चुकी है, लेकिन पाकिस्तान ने अक्लमंदी का परिचय देते हुए भारतीय पायलट को रिहा कर दिया और दोनों पक्ष युद्ध के मुहाने से आगे नहीं बढ़े। इसके बाद भारत में लोकसभा चुनावों के दौरान भी तेवर तीखे ही बने रहे, और इस बीच खान ने अप्रैल में एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी दोबारा चुनाव जीते तो दोनों देश शांति की दिशा में कदम बढ़ाएंगे (पटनायक 2022, पृष्ठ संख्या-9)। हुआ भी ऐसा ही। मोदी को चुनाव में भारी जीत मिली और दोनों देश भारतीय सिख तीर्थयात्रियों को बिना वीजा करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए गलियारा बनाने पर सहमत हुए। इसके लिए एक समझौते को औपचारिक रूप देने पर बातचीत शुरू हुई। रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलनी शुरू ही हुई थी कि मोदी सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने का ऐलान कर दिया। ऐसा ही एक फैसला था जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करना (जैकब 2015, पृष्ठ संख्या-1)। इसके बाद भारत-पाक संबंध फिर खराब होने लगे।

पाकिस्तान ने भारत के साथ कूटनीतिक संबंधों को कम कर दिया और भारतीय उच्चायुक्त को निर्वासित कर दिया। पाकिस्तान ने साथ ही भारत के साथ सभी वायु एवं भूमि संपर्क भी खत्म कर दिए और व्यापार तथा रेलवे गठजोड़ को भी खत्म कर दिया। इसके बाद करतारपुर गलियारे के भविष्य पर भी सवाल उठने लगे, जिसका उद्घाटन गुरुनानक देवजी के 550वें प्रकाश पर्व से पहले होना था। हालांकि आशंकाएं गलत साबित हुईं, और गलियारा समय पर चालू हुआ। पाकिस्तान और भारत ने नवंबर में अलग-अलग अपने तरफ के गलियारे का उद्घाटन किया (भारतीय वैश्विक परिषद 2022, पृष्ठ संख्या-1)।

दुर्भाग्यवश, इससे उत्पन्न सद्भावना दोनों देशों के बीच विश्वास को बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों में बहाल करने में सफल नहीं हो सकी। साल के अंत में भारत ने विवादित नागरिकता कानून पारित किया, इससे संबंधों में तनाव और बढ़ा। इस साल दोनों देशों ने पाकिस्तान में मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कानूनी लड़ाई भी लड़ी। इस फैसले से हालांकि जमीनी हालात में बहुत अंतर नहीं आया, लेकिन भारत को राजनयिक पहुंच मिली। इससे पहले पाकिस्तान लगातार भारत को राजनयिक पहुंच से इनकार कर रहा था।

भारत-पाक सम्बन्धों में अनेक विफलताएँ और सीमित निष्कर्ष देखे गये हैं। निरन्तर वैमनस्यता के कारण दोनों पक्षों की सीमाओं पर भू-राजनीतिक परिवेश को क्षति पहुँची है। तनाव होने के बावजूद दोनों देशों के नागरिक समाज के कुछ वर्गों ने लम्बित मुद्दों पर परिचर्चा तथा उसके समाधान पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है (विदेश मंत्रालय 2023, पृष्ठ संख्या-1)। चूँकि दोनों देशों की सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत एक जैसी है अत: यह विश्वास किया जाता है कि शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित एक ठोस सम्बन्ध का विकास निश्चित रूप से किया जा सकता है। द्विपक्षीय सम्बन्धों को उन्नत करने अथवा किसी भी एक पक्ष से सौहार्द्र प्रदर्शित करने के किसी प्रयास की प्राय: दोनों पक्षों से एक समान प्रतिक्रिया आती है। सिख तीर्थयात्रियों के लिए करतारपुर कारीडोर खोलने तथा दो सिख तीर्थस्थलों डेरा बाबा नानक साहिब (भारत) तथा करतारपुर साहिब (पाकिस्तान) को जोड़ने की हालिया घोषणा इस सम्बन्ध में एक सार्थक प्रगति है (भारतीय वैश्विक परिषद 2023, पृष्ठ संख्या-1)।

भारत-पाकिस्तान संबंध में प्रतिस्पर्धा और वैमनस्यता

भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध जम्मू-कश्मीर को लेकर लड़ा गया था। नव निर्मित पाकिस्तानी सेना की सहायता से सशस्त्र पाकिस्तानी आदिवासियों ने अक्टूबर 1947 में जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण किया। जम्मू और कश्मीर राज्य के कानूनी शासक, महाराजा हरि सिंह को आंतरिक विद्रोह के साथ-साथ बाहरी आक्रमण का सामना करना पड़ा, उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों से सहायता का अनुरोध किया। सेनाएँ और भारत में शामिल होने पर सहमत हुईं। उन्होंने अपनी रक्षा, संचार और विदेशी मामलों का नियंत्रण भारत सरकार को सौंप दिया।

1948 के उत्तरार्ध तक लड़ाई जारी रही। युद्ध आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1949 को समाप्त हुआ, जब संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने एक स्थापित युद्धविराम रेखा, एक संयुक्त राष्ट्र शांति सेना और सिफारिश के साथ युद्धविराम की व्यवस्था की कि जम्मू के विलय पर जनमत संग्रह कराया जाए (अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2023, पृष्ठ संख्या-1)। और कश्मीर को भारत में रखा जाए। पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर राज्य के लगभग एक-तिहाई हिस्से को नियंत्रित किया, इसे आज़ाद (स्वतंत्र) जम्मू और कश्मीर के रूप में संदर्भित किया और दावा किया कि यह अर्ध-स्वायत्त था। हुंजा और नगर के पूर्व साम्राज्यों सहित एक बड़े क्षेत्र को सीधे केंद्रीय पाकिस्तानी सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया था।

वर्ष 1965 में, भारत और पाकिस्तान ने अपना दूसरा युद्ध लड़ा, इससे पहले अप्रैल और सितंबर के बीच दोनों देशों के बीच झड़पें हुईं। युद्ध में दोनों तरफ से हजारों लोग हताहत हुए और इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बख्तरबंद वाहनों की सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे बड़ी टैंक लड़ाई देखी गई। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका (यू०एस०ए०) के राजनयिक हस्तक्षेप और उसके बाद ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य युद्धविराम की घोषणा के बाद यह समाप्त हो गया (अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2023, पृष्ठ संख्या-1)।

पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरे युद्ध का कारण बना। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच संघर्ष तब शुरू हुआ जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व वाली पश्चिमी पाकिस्तान में बैठी केंद्रीय पाकिस्तानी सरकार ने अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान, पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली, जिनकी पार्टी ने अधिकांश सीटें जीती थीं, को अनुमति देने से इनकार कर दिया। 1970 के संसदीय चुनाव परिणाम के बाद , देश का प्रधान मंत्री पद ग्रहण करने के लिए शेख़ मुजबिर रहमान को नहीं बुलाया गया (कपूर 2019, पृष्ठ संख्या-1)। पाकिस्तानी सेना ने 1971 में ढाका मार्च में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की जिसमें बड़ी संख्या में छात्र और शिक्षक मारे गए। दिसंबर में भारत इस संघर्ष में शामिल हो गया, जब पाकिस्तानी वायु सेना ने भारत के उत्तर-पश्चिम में हवाई क्षेत्रों पर एहतियाती हमला किया। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान पर समन्वित भूमि, वायु और समुद्री हमले के साथ जवाबी कार्रवाई की। इसने पाकिस्तानी सेना को ढाका में आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया और 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया गया। 6 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश, बांग्लादेश बन गया। जुलाई 1972 में, भारतीय प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष प्रधान मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारतीय शहर शिमला में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों देश "उस संघर्ष और टकराव को समाप्त करने पर सहमत हुए, जिसने अब तक द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित किया है।" और मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने और उपमहाद्वीप में टिकाऊ शांति की स्थापना के लिए काम करें ' (वैश्विक भारतीय परिषद 2023, पृष्ठ संख्या-1)। दोनों पक्ष किसी भी विवाद को "द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीकों से" निपटाने पर सहमत हुए ।

शिमला समझौते ने 17 दिसंबर 1971 की युद्धविराम रेखा को दोनों देशों के बीच नई "नियंत्रण रेखा (एलओसी)" के रूप में नामित किया, जिसे किसी भी पक्ष को एकतरफा रूप से बदलने की कोशिश नहीं करनी थी, और जिसका "दोनों पक्षों द्वारा बिना किसी पूर्वाग्रह के सम्मान किया जाएगा" दोनों पक्षों की मान्यता प्राप्त स्थिति" । शिमला समझौते को 1972 में भारत और पाकिस्तान दोनों की संसदों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

कश्मीर घाटी में सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ। मुस्लिम राजनीतिक दलों ने, राज्य सरकार पर 1987 के राज्य विधान चुनावों में धांधली का आरोप लगाने के बाद, उग्रवादी विंग का गठन किया। पाकिस्तान का कहना है कि वह उग्रवादियों को "नैतिक और कूटनीतिक" समर्थन प्रदान कर रहा था। हालाँकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह व्यापक रूप से माना जाता है कि पाकिस्तान वास्तव में लड़ाकों को धन, निर्देश, आश्रय, हथियार और प्रशिक्षण प्रदान करके विद्रोह को बढ़ावा देने में शामिल है। भारत का मानना है कि जम्मू-कश्मीर में उसकी सेना के खिलाफ सशस्त्र हमले पाकिस्तान की सहायता से किया जा रहा है (मनोहर पर्रिकर रक्षा एवं विश्लेषण संस्थान 2023, पृष्ठ संख्या-1)।

पाकिस्तान द्वारा 'हजारों वार करके भारत का खून बहाने' की नीति के तहत 'सीमा पार आतंकवाद' की स्पष्ट अभिव्यक्ति हैं । पाकिस्तान इससे इनकार करता है। कश्मीर घाटी में लड़ाई में भाग लेने वाले उग्रवादी समूह 1990 के दशक तक उभरते रहे, उनके रैंकों को युद्ध-कठिन "मुजाहिदीन" की एक बड़ी आमद से बल मिला , जिन्होंने पहले सोवियत संघ के खिलाफ अफगान युद्ध में भाग लिया था। जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों, हिंदुओं और बौद्धों के बीच सदियों से सांप्रदायिक सद्भाव के बावजूद, कश्मीर घाटी में जम्मू और कश्मीर के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय (कश्मीरी पंडित) को आतंकवादियों ने निशाना बनाया और पलायन करने के लिए मजबूर किया (अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2023, पृष्ठ संख्या-1)।

भारत ने पोखरण में पांच परमाणु उपकरण विस्फोट किये। पाकिस्तान ने चघाई पहाड़ियों में अपने छह परमाणु उपकरणों को विस्फोट करके जवाब दिया। परीक्षणों के परिणामस्वरूप दोनों देशों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए। दोनों देश नवीनतम परमाणु-सशस्त्र राष्ट्र बन गए। भारतीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधान मंत्री नवाज शरीफ से मिलने के लिए बस से लाहौर (नई खुली दिल्ली-लाहौर बस सेवा) की यात्रा की। दोनों ने लाहौर घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जो 1972 के शिमला समझौते के बाद दोनों देशों के बीच पहला बड़ा समझौता था। दोनों देशों ने दोहराया कि वे शिमला समझौते के प्रति प्रतिबद्ध हैं, और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार लाने के उद्देश्य से कई विश्वास निर्माण उपाय (सीबीएम) करने पर सहमत हुए (कपूर 2015, पृष्ठ संख्या-2)।

मई में, कारगिल संघर्ष तब छिड़ गया जब पाकिस्तानी सेनाओं ने घुसपैठ की और एलओसी के भारतीय पक्ष पर रणनीतिक पदों पर कब्जा कर लिया, जिससे भारतीय जवाबी हमला हुआ जिसमें पाकिस्तानी सेनाओं को मूल एलओसी के उनके पक्ष में वापस धकेल दिया गया। आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार परीक्षण करने के बाद कारगिल दोनों पड़ोसियों के बीच पहला सशस्त्र संघर्ष था। इस संघर्ष के बढ़ने की संभावना और इसके व्यापक प्रभावों को देखते हुए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तानी प्रधान मंत्री नवाज शरीफ को बुलाया और उनसे अपने सैनिकों पर लगाम लगाने की मांग की (जैकब 2015, पृष्ठ संख्या-1)।

13 दिसंबर को नई दिल्ली में भारतीय संसद पर एक सशस्त्र हमले में 14 लोग मारे गए। हमलों के लिए लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को ज़िम्मेदार ठहराया गया। हमलों के कारण नियंत्रण रेखा पर भारत और पाकिस्तान की सेनाएं एकत्र हो गईं। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के बाद अक्टूबर 2002 में ही गतिरोध समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री वाजपेयी और राष्ट्रपति मुशर्रफ ने जनवरी में इस्लामाबाद में 12वें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलन में सीधी बातचीत की और दोनों देशों के विदेश सचिवों ने वर्ष के अंत में मुलाकात की। इस वर्ष समग्र वार्ता प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जिसमें सरकार के विभिन्न स्तरों (विदेश मंत्रियों, विदेश सचिवों, सैन्य अधिकारियों, सीमा सुरक्षा अधिकारियों, मादक द्रव्य विरोधी अधिकारियों और परमाणु विशेषज्ञों सहित) के अधिकारियों के बीच द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं (ग्रारे 2015, पृष्ठ संख्या-1)। नवंबर में, जम्मू और कश्मीर की यात्रा की पूर्व संध्या पर, नए भारतीय प्रधान मंत्री, मनमोहन सिंह ने घोषणा की कि भारत वहां अपने सैनिकों की तैनाती कम करेगा।

26 नवंबर को, दुनिया के सबसे भीषण आतंकवादी हमलों में से एक में, सशस्त्र बंदूकधारियों ने भारत के मुंबई में कई स्थानों पर नागरिकों पर गोलीबारी की। जिन स्थानों पर हमला किया गया उनमें ताज महल पैलेस और टॉवर, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, छत्रपति शिवाजी ट्रेन टर्मिनस, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल, नरीमन हाउस यहूदी सामुदायिक केंद्र, मेट्रो सिनेमा, सेंट जेवियर्स कॉलेज और टाइम्स ऑफ इंडिया कार्यालय के पास एक गली शामिल थी। हमलों में 160 से ज्यादा लोग मारे गये थे. ताज की लगभग तीन दिनों की घेराबंदी, जहां बंदूकधारी तब तक छिपे रहे जब तक कि भारतीय सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में उनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी लोग मारे नहीं गए, हताहतों की संख्या का बड़ा कारण यही था। जिंदा पकड़े गए एकमात्र हमलावर अजमल कसाब ने कबूल किया कि हमलावर लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थे। ट्रैकिंग कॉल और संचार सभी पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, जहां से पूरे

हमले की साजिश रची गई और निर्देशित किया गया। हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान से बातचीत तोड़ दी। पाकिस्तानी सरकार ने स्वीकार किया कि मुंबई हमलों की योजना पाकिस्तानी धरती पर बनाई गई थी, लेकिन इस बात से इनकार किया कि साजिशकर्ताओं को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों द्वारा मंजूरी दी गई थी या सहायता मिली थी। हालाँकि, भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ कड़ा रुख अपनाना जारी रखा, उसकी गठबंधन सरकार ने कहा कि यह पाकिस्तान पर निर्भर है कि वह अपनी धरती पर आतंकवादी समूहों पर नकेल कस कर ठोस बातचीत फिर से शुरू करने की दिशा में पहला कदम उठाए। सितंबर में, भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर न्यूयॉर्क में मुलाकात की। वे जम्मू-कश्मीर के विवादित क्षेत्र में दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच तनाव समाप्त करने पर सहमत हुए। भारत की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पार्टी मार्च में स्थानीय पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के साथ गठबंधन में भारत प्रशासित जम्मू और कश्मीर में सरकार बनाती है। पीडीपी प्रमुख मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दिसंबर में, अफगानिस्तान से वापस आते समय, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान मंत्री नवाज शरीफ के जन्मदिन और उनकी पोती की शादी पर लाहौर का अचानक दौरा करते हैं (मित्रा 2017, पृष्ठ संख्या-264)।

जनवरी में सैनिकों के भेष में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने भारत के उत्तर-पश्चिमी राज्य पंजाब में पठानकोट एयरबेस पर घातक हमला किया। यह हमला द्विपक्षीय वार्ता को पुनर्जीवित करने के प्रयास में प्रधान मंत्री मोदी द्वारा पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ की अचानक यात्रा के एक सप्ताह बाद हुआ है (अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2023, पृष्ठ संख्या-1)। सितंबर में, जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर के उरी में एक सैन्य अड्डे पर हमला किया और 17 भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी। 29 सितंबर को, भारत ने उरी में हमले के लिए अपनी पहली प्रत्यक्ष सैन्य प्रतिक्रिया में, पाकिस्तान प्रशासित जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार संदिग्ध आतंकवादियों पर 'सर्जिकल हमले' किए।

14 फरवरी को भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में एक आत्मघाती बम विस्फोट में भारतीय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 40 सदस्य मारे गए। दशकों में अशांत क्षेत्र में भारतीय बलों पर यह सबसे घातक हमला है। 15 फरवरी को, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन, जैश ए मोहम्मद, हमले का दावा करता है और आत्मघाती हमलावर की पहचान करते हुए एक वीडियो जारी करता है। दो दिन बाद, भारत ने तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से सभी आयातों पर शुल्क 200 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। 18 फरवरी को, एक विनाशकारी आत्मघाती बम विस्फोट को अंजाम देने के कुछ दिनों बाद, जिसमें 40 भारतीय सुरक्षा बल मारे गए, जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना के एक मेजर और कम से कम तीन अन्य सैनिकों की हत्या कर दी। कथित तौर पर, जैश-ए-मोहम्मद के एक कमांडर सहित दो आतंकवादी, जिन्हें 14 फरवरी को हुए हमले का मास्टरमाइंड माना जाता था, भारतीय सेना के साथ गोलीबारी में मारे गए।

पाकिस्तानी प्रधान मंत्री इमरान खान ने 19 फरवरी को 14 फरवरी को पुलवामा हमले के संबंध में भारत के साथ बातचीत और सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की। भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि "हम करारा जवाब देंगे, हमारे पड़ोसी को हमें अस्थिर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी" (भारतीय वैश्विक परिषद 2023, पृष्ठ संख्या-1)। 25 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच गोलीबारी हुई। 26 फरवरी को, भारत सरकार ने पाकिस्तानी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में बालाकोट के पास पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जेईएम के 'सबसे बड़े प्रशिक्षण शिविर' को निशाना बनाते हुए 'गैर-सैन्य पूर्व-खाली' हमले किए। शुरुआत में इस बात से इनकार करने के बाद कि ऐसी कोई घटना हुई है, पाकिस्तान ने बाद में स्वीकार किया कि भारतीय लड़ाकू विमान वास्तव में बिना पहचाने पाकिस्तानी क्षेत्र में काफी अंदर तक घुस गए थे और बालाकोट के पास बम गिराए थे।

हालांकि, पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि हमले एक खाली इलाके में

हुए। 27 फरवरी को पाकिस्तानी सेना ने चेतावनी दी कि वह भारत की हवाई बमबारी का जवाब देगी। भारतीय वायु सेना ने एक पाकिस्तानी F–16 लड़ाकू विमान को मार गिराया, जबकि पाकिस्तान ने दो भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया और एक भारतीय पायलट को पकड़ लिया। 28 फरवरी को, इमरान खान का कहना है कि पकड़े गए भारतीय वायु सेना के पायलट को "शांति संकेत" के रूप में रिहा कर दिया जाएगा। रिपोर्टों से पता चलता है कि पाकिस्तानी प्रधान मंत्री अंतरराष्ट्रीय दबाव में हो सकते हैं, खासकर अमेरिका से। अप्रैल के पहले सप्ताह में, भारत और पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में गोलीबारी की, जिसमें सात लोग मारे गए।

25 फरवरी को, भारत और पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों देशों की सेनाओं द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि उनके शीर्ष अधिकारी संघर्ष विराम का सख्ती से पालन करने और संभावित गलतफहमी को हल करने के लिए हॉटलाइन के माध्यम से संचार जारी रखने पर सहमत हुए हैं। संघर्ष विराम के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता की खबर का विशेष रूप से वास्तविक सीमा, एलओसी पर रहने वाले समुदायों द्वारा स्वागत किया गया, जिन्होंने दोनों पक्षों की झड़पों का खामियाजा भुगता है। 3 मई को, पाकिस्तान ने रामगढ़ सेक्टर में अकारण गोलीबारी करके संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया। पूरे 2021 में दोनों पक्षों द्वारा कई अन्य उल्लंघनों की भी सूचना दी गई, हालांकि, इनसे क्षेत्र की स्थिरता में कोई बाधा नहीं आई है और संघर्ष विराम अब तक सक्रिय है।

निष्कर्ष:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई बार गंभीर प्रयास करने के बावजूद भारत, पाकिस्तान के साथ अपने ख़राब रिश्तों को दुरुस्त कर पाने में नाकाम रहा है। इसके बजाय, भारत के तमाम प्रयासों की नाकामी ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने और रिश्ते सुधारने को लेकर भारत के सुरक्षा तंत्र के नाउम्मीदी भरे नज़रिए को ही मज़बूती दी है। इसके अलावा सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय होड़ और सैन्य, आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक प्रभाव के मामले में दोनों देशों के बीच बढ़ते अंतर ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बदलाव की उम्मीदों को भी काफ़ी सीमित कर दिया है। हो सकता है कि पाकिस्तान, जियोइकॉनमिक्स के पर्दे की आड़ में अपनी भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को छुपाना चाहे. लेकिन वो इस क्षेत्र को अस्थिर बनाने में अपनी नकारात्मक भूमिका पर पर्दा नहीं डाल सकता है। जब तक पाकिस्तान का शासक वर्ग और सैन्य तंत्र कश्मीर, आतंकवादी संगठनों को मदद और भारत विरोधी दुष्प्रचार की अपनी नीति में बुनियादी तौर पर बदलाव नहीं लाते हैं, तब तक भारत द्वारा अपने रुख़ में कोई बदलाव करने की कोई संभावना नहीं दिखती है।

पाकिस्तान और भारत 2019 में उस समय युद्ध के कगार पर आ खड़े हुए थे, जब पुलवामा आंतकी हमले में दर्जनों सीआरपीएफ के जवान मारे गए और उसके बाद भारत को पाकिस्तान स्थित आंतकी शिविरों पर हवाई हमला करने के लिए बाध्य होना पड़ा। हालांकि, साल का अंत एक सकारात्मक घटनाक्रम से हुआ और पाकिस्तान ने सिख तीर्थयात्रियों के लिए ऐतिहासिक करतारपुर गलियारे का उद्घाटन किया। इस गलियारे के जरिए बिना वीजा के करतारपुर साहिब के दर्शन किए जा सकते हैं।

संदर्भ

1. भारतीय वैश्विक परिषद (2019), करतारपुर साहिब कॉरिडोर: भारत-पाक संबंधों की रजत रेखा?, URL: https://www.icwa.in/show_content.php?lang
2. दक्षिण एशिया के लिए यूरोपीय फ़ाउंडेशन (2023), भारत-पाक संबंध - एक संक्षिप्त इतिहास, URL: https://www.efsas.org/topics/indo-pak-relations.html
3. अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन (2023), भारत-पाक संबंध: पाकिस्तान की भारत विरोधी सुरक्षा रणनीति से कैसे निपटें?, URL: https://www.orfonline.org/hindi/expert-speak/indo-pak-relations-how-to-deal-with-pakistans-anti-india-security-strategy
4. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार (2023), भारत-पाकिस्तान संबंध, FFF: https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Pakistan_April2014_hindi.pdf

5. मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (2023), भारत-पाकिस्तान संबंध, URL: https://idsa.in/taxonomy/term/195
6. हुसैन, एजाज़ (2019), "भारत-पाकिस्तान संबंध : चुनौतियाँ एवं अवसर" , सेज जर्नल, वॉल्यूम-1, संख्या -1, पृष्ठ संख्या- 1-16
7. पटनायक, स्मृति (2022), "भारत-पाकिस्तान संबंध" , आई०डी०एस०ए०, वॉल्यूम-1, संख्या-1, पृष्ठ संख्या-1-12
8. मेहता, प्रताप भानु (2022), "भारत-पाकिस्तान संबंध" , पोलिटिकल एंड इकोनोमिक वीक्ली, वॉल्यूम-1, संख्या-1, पृष्ठ संख्या-1-10
9. प्रसाद, नितिन (2017), पाकिस्तान के लिए भारत की विदेश नीति में परिवर्तन, नई दिल्ली : अल्फ़ा इडिशन
10. पड्डेर, सजाड (2022), भारत-पाकिस्तान संबंध के सत्तर साल, नई दिल्ली: रूतलेज पब्लिकेशन
11. श्रीधरन, ई० (2007), अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सिद्धांत एवं भारत-पाकिस्तान संबंध में तनाव, नई दिल्ली: रूतलेज पब्लिकेशन
12. कपूर, अशोक (2019), भारत-पाकिस्तान संबंध, नई दिल्ली : रूतलेज पब्लिकेशन
13. जैकब, हैपीमोन (2016), "भारत-पाकिस्तान संबंध: विवाद एवं समाधान" , सेंटर फ़ोर एशियन स्टडीज़, वॉल्यूम-1, संख्या-1, पृष्ठ संख्या-1-12
14. मित्तल, देविका एवं रंजन, अमित (2016), "भारत-पाकिस्तान संबंध" , जर्नल ऑफ़ स्पेस एंड कल्चर इंडिया, वॉल्यूम-4, संख्या-1, पृष्ठ संख्या-1-22
15. मित्रा, सुब्रत (2017), "भारत-पाकिस्तान संबंध" , जर्नल ऑफ़ इंडिया रिव्यू, वॉल्यूम-16, संख्या-2, पृष्ठ संख्या-266-276
16. ग्रारे, फ़्रेड्रिक (2015), "भारत-पाकिस्तान संबंध: मोदी प्रभाव" , द वाशिंगटन क्वाटरली, वॉल्यूम-37, संख्या-4, पृष्ठ संख्या- 101-114